

[Dr. V. Kulandaivelu]

In view of protecting the interests of the local people of Pondicherry Union Territory, the new concept should be withdrawn forthwith.

I may add that last year three Scheduled Caste candidates were denied admission to the MBBS Course at Jawaharlal Institute of Post Graduate Medical Education and Research, Pondicherry in the name of so-called merits and eligibility in the entrance examination. It has been our observation that there was no proven method to assess the intellectuality of an individual. As is the case, it is highly cruel to deny admission to the underprivileged communities who aim at higher education and training with all obstacles on their way. Keeping these points in mind, I plead with the Minister for Health and Family Welfare, Government of India, to ensure avenues of admissibility of the Scheduled Castes and Tribes with the suitable relaxation of rules and regulations.

(vii) ALLEGED DISPOSSESSION OF LANDS OWNED BY THE FARMERS AROUND PATNA CITY

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : पटना बिहार की राजधानी है। इस नगर की आबादी सन् 1981 की जन गणना के अनुसार आठ लाख से अधिक हो चुकी है।

पटना नगर में शेखपुरा, इस से सटे दीघा, कुर्जी, शहर के मध्य में कंकड़बाग से सटे ग्राम चांगर, विग्रहपुर, नवरत्नपुर, संदलपुर आदि में जो जमीन सरकारी चंगुल से बची हुई है उन जमीनों पर भी उसकी गिद्ध दृष्टि लगी हुई है। हजारों किसान-मजदूर उन जमीनों पर सब्जी आदि की खेती कर पटना के नागरिकों को हरी सब्जियां तो खिलाते ही हैं, उनकी आय से वे अपने परिवार का भरण-पोषण भी करते हैं। दीघा का सफेद मालदह आम तो जगत प्रसिद्ध रहा है। पर किसानों से

जमीन छीनने के क्रम में उसका भी प्रायः सत्यानाश कर दिया गया है।

इस प्रकार से सरकार किसानों से जो जमीन अर्जित कर रही है उस पर बड़े लोगों की कालोनियों, सरकारी महलों को खड़ा कर किसानों को भूखों मारने का कुचक्र रच रही है। फलस्वरूप किसानों में भयंकर रोष और क्षोभ है तथा इस प्रकार से किसानों को उजाड़ने की नीति के विरुद्ध आन्दोलन विकसित हो रहा है। किसानों का कहना है कि वे कारखाने खोलने, सरकारी उपयोग के लिए भवन बनाने के विरुद्ध नहीं हैं। परन्तु सहयोग समितियों, कालोनियों, महलों के निर्माण के लिए वे अपनी रोजी-रोटी के साधन छोड़ने के लिए कतई तैयार नहीं हैं। उनकी यह मांग है कि शहरों में जिन किसानों की जमीन अर्जित की जाये उनके कम से कम एक लड़के या परिवार के सदस्य को नौकरी दी जाये, उनके लिए रहने और रोजगार की वैकल्पिक व्यवस्था की जाए।

इन बातों का समावेश करते हुए ऐसा कोई कानून बनाया जाए जिससे किसानों को जमीन विहीन हो कर दर-दूर का भिखारी नहीं बनना पड़े। आशा है, सरकार का ध्यान इस महत्वपूर्ण समस्या की ओर आकृष्ट होगा।

(vii) NEED TO BRING CHINSURAH GROUP OF TELEPHONES WITHIN THE CALCUTTA LOCAL SYSTEM

PROF. RUP CHAND PAL (Hooghly): Sir, Chinsurah being the Divisional Headquarter of Burdwan division, as also the district headquarter of Hooghly district in West Bengal, is a very important town, both from the administrative and the business point of view. But the Chinsurah Telephone Exchange has been kept outside the Calcutta Local Telephone System although towns of lesser importance had long ago been brought within the Calcutta Local Telephone System. Prior to February, 1973, Chinsurah was connected to